



राष्ट्र की आवाज

# आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ, गुरुवार 18 अप्रैल, 2019, मूल्य 1 रुपये



मलाइका की खूबसूरती का राज-पेज 4

## भारतीय शिक्षण प्रणाली व इंजीनियरिंग की स्थिति : एक आंकलन

लखनऊ-आर्यावर्त ब्यूरो

हम यह भलीभांति जानते हैं कि किसी देश के विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे भविष्य में राष्ट्र का स्वरूप व दिशा निर्धारण करते हैं। शिक्षक बच्चों को कुम्हार की भांति गढ़ता है और वांछित स्वरूप प्रदान करता है। इस गुरुत्व दायित्व के निर्वहन के लिए शिक्षकों को बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिये। यशपाल समिति की रिपोर्ट (1993) ने माना है कि शिक्षकों की तैयारी के अपर्याप्त अवसर से स्कूल में अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन कार्यक्रमों की विषयवस्तु इस प्रकार पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए कि स्कूली शिक्षा की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं में स्व-शिक्षण और स्वतंत्र चिंतन की क्षमता के विकास



पर जोर देना होगा।

कोटारी आयोग (1964-66) की रिपोर्ट से, यह बात की जाने लगी थी कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों को बतौर पेशेवर तैयार करना अत्यंत जरूरी है। आज एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह बच्चों को जाने, समझे, कक्षा में उनके व्यवहार को

समझे, उनके सीखने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करे, उनके लिए उपयुक्त सामग्री व गतिविधियों का चुनाव करे, बच्चे की जिज्ञासा को बनाए रखे, उन्हें अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करे व उनके अनुभवों का सम्मान करे। तात्पर्य यह है कि आज की जटिल परिस्थितियों में शिक्षकों की भूमिका कहीं

अधिक

उत्तरदायित्वपूर्ण व महत्वपूर्ण हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक-शिक्षा को और कागर बनाने की आवश्यकता है। शिक्षक-शिक्षा में आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता बताते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा-

2005 में शिक्षकों की भूमिका के संबंध में कहा गया है कि सीखने-सिखाने की परिस्थितियों में उत्साहवर्धक सहयोगी तथा सीखने को सहज बनाने वाले बनें जो अपने विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभाओं की खोज में, उनकी शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताओं को पूर्णता तक जानने में, उनमें अपेक्षित सामाजिक तथा



डॉ. भरत राज सिंह  
वरिष्ठ पर्यावरणविद व महानिदेशक  
(तकनीकी), एसएमएस, लखनऊ

होना होगा तथा शिक्षण के तरीकों पर जोर देने के स्थान पर विषय की समझ को महत्व दिया जाना चाहिये। उपरोक्त क्रम में, भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा का काफी विकास हुआ और इंजीनियरिंग शिक्षा में विशेष सुधार की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजों का आकलन, रुचि व कारण

मानवीय मूल्यों व चरित्र के विकास में तथा जिम्मेदार नागरिकों की भूमिका निभाने में समर्थ बनाए। प्रश्न यह है कि शिक्षक को बच्चों में शिक्षा की समझ, विषयों की समझ, सीखने के तरीके की समझ, समाज व शिक्षा का संबंध जैसे पहलुओं पर केन्द्रित

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के 2017 के आकड़े के अनुसार भारत में कुल 10,345 इंजीनियरिंग कालेज हैं जिनमें से मात्र 396 इंजीनियरिंग कालेज गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं शेष इंजीनियरिंग कालेज एक फ़ैक्टरी के रूप में शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत से प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियरों ने विदेशों में अपनी पहचान बनाई है। इसके बावजूद सच्चाई यही है कि भारतीय संस्थानों से निकलने वाले अधिकांश छात्र नौकरी पाने के लिए जरूरी पात्रता नहीं रखते। हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि लगभग 80 फीसदी भारतीय इंजीनियरिंग छात्रों में रोजगार की योग्यता ही नहीं है। नेशनल इम्प्लायबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 80 फीसदी इंजीनियर रोजगार के काबिल नहीं हैं। रिपोर्ट में 650 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों के

1,50,000 इंजीनियरिंग छात्रों का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत है ताकि वे श्रम बाजार की जरूरतों के हिसाब से काबिल हो सकें। रिपोर्ट में दिल्ली के संस्थानों को योग्य इंजीनियर देने में बेहतर बताया गया है। इसमें दूसरा स्थान बंगलूरु का है और इसके बाद मुंबई और पुणे के कॉलेजों का नंबर आता है। वैसे रिपोर्ट के अनुसार छोटे शहरों से भी रोजगार की योग्यता रखने वाले इंजीनियर निकल रहे हैं। राज्यों की बात करें तो बिहार-झारखंड, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड की स्थिति थोड़ी ठीक है। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां के कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों की रोजगार पात्रता बहुत ही कमजोर होती है।